2 वर्षों में आग से 160 लोगों की मौत

मालवीय नगर आग हादसे पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, सहायता राशि की घोषणा

नई दिल्ली ,03 जून.दिल्ली में आगजनी की घटनाओं ने पूरे देश को गहरे सदमें में डाल दिया है.यह पहली बार नहीं है कि दिल्ली आग में की जल रही है. पिछले दो साल की बात करें तो, इस तरह के आगजनी में अब तक 160 लोग झुलस गए हैं. लेकिन अब तक इन घटनाओं से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है.

पीएम नरेन्द्र मोदी ने मालवीय नगर में बुधवार सुबह एक होटल में आग लगने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और इस हादसे में मारे गये लोगों के परिजनों एवं घायलों के लिये सहायता राशि की घोषणा की है.प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो - दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे. पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना एक दुखद घटना है.

खरगे, राहुल, प्रियंका ने मालवीय नगर अग्निकांड पर जताया शोक

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राष्ट्रीय राजधानी के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। कांग्रेस नेताओं ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव में पूरा सहयोग करने की अपील करते हुए सरकार से पीड़ित परिजनों को सहायता देने का भी आग्रह किया है.

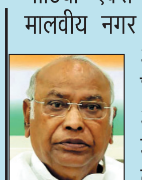

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मालवीय नगर में हुई दुखद अग्निकांड की घटना से वह अत्यंत दुखी हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों को समय पर तथा पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराना चाहिए.

राहुल गांधी ने कहा कि मालवीय नगर में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत एवं बचाव कार्यों में हरसंभव योगदान देने की अपील की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की.

प्रियंका ने कहा कि होटल में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु तथा 36 से अधिक लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकसंतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यथासंभव सहायता करने की अपील भी की है.

अग्निकांड में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा : सूद

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि मालवीय नगर हादसे के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. श्री सूद ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि इमारत मालिक और लापरवाही बरतने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लोगों ने कूदकर बचाई जान.

प्रमुख बिंदु....

- इस घटना में 6 कांस्टेबल, और 6 हेड कांस्टेबल लोगों की जान बचाने में जख्मी हो गए. जिनको एम्स में भर्ती किया गया.
- होटल में केवल एक ही मुख्य प्रवेश और निकास मार्ग होने से रेस्क्यू में बाधा आई.
- सूत्रों के अनुसार, होटल को 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे.
- क्षमता से अधिक करीब 40 मेहमानों को होटल में ठहराए जाने की बात सामने आई है.
- तीन पार्टनर मिलकर ये होटल चला रहे थे. होटल का मालिक का नाम लोकेश बजाज है.
- आग की शुरुआत बेसमेंट स्थित रेस्टोरेंट 'लेमन ग्रीन' से हुई.
- बचाव अभियान में पुलिस, दमकल और आपातकालीन टीमों ने 40 से अधिक लोगों को निकाला
- मैक्स अस्पताल में 39 घायलों को लाया गया, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई गई.
- घायलों में 9 भारतीय और 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं.

मुंबई में हल्की बौछारों से यातायात ठप

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगी लंबी कतारें

मुंबई, 3 जून. मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार को हुई हल्की से मध्यम मानसून-पूर्व की बौछारों के कारण मुख्य सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया और सुबह के व्यस्त समय के दौरान हजारों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (डब्ल्यूईएच), ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (ईईएच), जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (जेवीएलआर) और पवई के कुछ हिस्सों में शहर में हुई बरसात के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गयीं. महालक्ष्मी, मरीन ड्राइव, बांद्रा, अंधेरी, विले पार्ले, कांदिवली, मीरा रोड, विरार, घाटकोपर, मुलुंड और कुर्ला के

कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बौछारें दर्ज की गयीं. यातायात में यह व्यवधान ऐसे समय में हुआ जब बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) शहर भर में मानसून की तैयारियों के उपाय कर रहा है. शहर के प्रमुख नालों की गाद निकालने और सफाई करने कचरे के ढेरों को हटाने और सड़कों के कंक्रीटीकरण का काम चल रहा है. यात्रियों ने वाकोला ब्रिज, कलिना और जोगेश्वरी फ्लाईओवर के पास यातायात की गति धीमी होने की शिकायत की, जबकि मुलुंड और कांजुरमार्ग के बीच के हिस्से में थोड़ी देर की बारिश के बाद भारी जाम देखा गया. कई वाहन चालकों ने ट्रैफिक जाम के हालात के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की.

राज्य का दर्जा बहाली समेत कई मुद्दों पर मंथन

श्रीनगर, 03 जून. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ यहां डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की. राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी और अन्य अहम मुद्दों को लेकर बढ़ती राजनीतिक चिंताओं के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. श्री अब्दुल्ला ने इसे ऑफ-साइट बैठक बताया. सीमित मोबाइल नेटवर्क वाले इस स्थान पर आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी विधायक और सांसद पहले मुख्यमंत्री के गुपकार रोड स्थित निजी कार्यालय पहुंचे, जहां से उन्हें बसों में बैठाकर डाचीगाम ले जाया गया.

सरकार की नयी कृषि कर्ज माफी योजना पर छिड़ा सियासी घमासान

सरकार के कदम से लाखों किसानों को मिलेगी राहत

मुंबई, 03 जून. महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों के लिए दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी को मंजूरी दिए जाने के फैसले के बाद राज्य में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. जहां एक ओर महायुति सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस योजना की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक धोखा, राजनीतिक स्टंट और किसान समुदाय के साथ एक क्रूर मजाक करार दिया है. कैबिनेट बैठक के दौरान, सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026% की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच वितरित किए गए अल्पकालिक फसल ऋण को माफ करना है.

इस पैकेज में उन किसानों के लिए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी शामिल है, जिन्होंने नियमित रूप से अपने कर्ज का भुगतान किया है. हालांकि, कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इस राहत के साथ जुड़ी शर्तों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

एक नजर में

सालाना 4 लाख आमदनी वालों को भी मिलेगा लाभ

पटना, 3 जून. बिहार सरकार ने राज्य के निवासियों खासकर गरीब वर्ग के लोगों के लिए ईलाज की सुविधा बढ़ा दी है और अब सालाना 4 लाख रुपये की आमदनी वाले लोगों को भी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना का लाभ

मिलेगा. पहले यह वार्षिक आय सीमा 2 लाख 50 हजार रुपये ही थी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस आय सीमा को बढ़ाते हुए 4 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय से बड़ी संख्या में राज्य के नागरिकों को लाभ मिलेगा. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने आज संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी. उन्होंने कहा कि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के तहत भोजपुर जिला में बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना करने के लिए राशि जारी की गई. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत इस पार्क की स्थापना की गई है. इसमें केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर 31 करोड़ 20 लाख 92 हजार रुपये दिए गए हैं. इससे राज्य के मात्स्यिकी एवं जल कृषि की संपूर्ण वैल्यू चेन एवं आधारभूत संरचनाओं के साथ-साथ मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक बढ़ोतरी, मत्स्य प्रसंस्करण, व्यापार, वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक की प्रशिक्षण तथा मनोरंजन गतिविधियों का समेकित रूप से समग्र विकास होगा।

निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकार्ड बनायेंगे मोदी

नई दिल्ली, 03 जून. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी दस जून को आजाद भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकार्ड बनायेंगे. अभी तक यह रिकार्ड देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के

नाम था. श्री मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इसके बाद से वह देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार काम कर रहे हैं. आगामी दस जून को प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो जायेंगे. यह पंडित नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4398 दिन के कार्यकाल से अधिक है. पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे. वैसे पंडित नेहरू आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे लेकिन तब वह निर्वाचित नहीं बल्कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री थे. इससे पहले श्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिन के कार्यकाल से आगे निकल गये थे. श्रीमती गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रही थी. यद्यपि वह बाद में 1980 में भी प्रधानमंत्री चुनी गयी थी. श्री मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भी 9000 से भी अधिक दिन तक कार्य कर चुके हैं. उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 2024 को शपथ ली थी. सूत्रों के अनुसार दस जून को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी.

आज का इतिहास

- 1896 – हेनरी फॉर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में अपना पहला मॉडल परीक्षण के लिए उतारा.
- 1929 – जॉर्ज ईस्टमेन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया.
- 1946 – भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्वगायकों में से एक एस. पी. बालासुब्रमण्यम का जन्म.
- 1959 – सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की.
- 1962 – आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रसिद्ध अचंत लक्ष्मीपति का निधन.
- 1964 – मालदीव ने संविधान का निर्माण किया.
- 1970 – ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्र देश बना.

पूर्वोत्तर परिषद के 73वां पूर्ण सत्र का आज

- 2026 को शिलांग में आयोजन
- गृहमंत्री शाह करेंग अध्यक्षता

नई दिल्ली, 3 जून . पूर्वोत्तर परिषद का 73 वां पूर्ण सत्र गुरुवार को मेघालय के शिलांग में आयोजित किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री और परिषद के अध्यक्ष अमित शाह करेंगे.

स बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया; विभाग के राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार; पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के राज्यपाल और

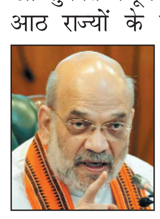

मुख्यमंत्री; परिषद के अन्य सदस्य; और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे. डोनर मंत्रालय की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार परिषद की इस बैठक से पहले वहां आज बांस, अगरवुड और क्षेत्र में पर्यटन से जुड़ी अष्टलक्ष्मी दर्शन जैसी प्रमुख पहलों और अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए बुधवार को बैठक आयोजित की गयी है.

जापान में तूफान ने मचायी तबाही

60 हजार घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित

900 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं

टोक्यो, 03 जून. उष्णकटिबंधीय भीषण तूफान जोंगमी के चलते तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने बुधवार सुबह जापान के विभिन्न हिस्सों में कहर बरपाया जिससे लगभग 60 हजार से घर प्रभावित हुए हैं.

जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि तूफान का केंद्र मुख्य मध्य द्वीप होंशू से दूर था, जो 25 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम निरंतर हवा की गति के साथ उत्तर-पूर्व में ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था. सरकारी प्रवक्ता मिनोरू किहारा ने नियमित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस सीजन का यह छठा चक्रवाती तूफान है. इसके स्तर को कम कर उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल दिया गया था, उसका केंद्रीय दबाव 980 एचपीए है. तूफान के कारण बुधवार सुबह करीब 900 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गयीं. इसकी वजह से लगभग 60,000 घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है.

श्री किहारा ने लोगों को सलाह दी, अगर आपको किसी भी खतरे का आभास होता है, तो कृपया अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने में संकोच न करें।दक्षिण-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी जापान के आठ प्रांतों में लाखों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गयी थी.

भ्रामक सूचनाओं के प्रति रहें सतर्क : ज्ञानेश

नई दिल्ली, 03 जून. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को यहां चुनाव अधिकारियों को जन संचार माध्यमों से जुड़े विषयों पर उत्तम वैश्विक प्रथाओं और उदाहरणों से परिचित कराने, दुष्प्रचार तथा भ्रामक सूचनाओं के प्रति सतर्क रखने के उद्देश्य से राजधानी में आयोजित दो दिन के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया.

यहां इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर केंद्रित इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में

अपने मुख्य भाषण में श्री कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव आयोग 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) और बूथ स्तरीय एजेंटों सहित जमीनी स्तर के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है.

हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभाओं चुनावों में मतदाताओं की अभूतपूर्व भागीदारी का उल्लेख करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास महत्वपूर्ण है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आइडिया) की 2026 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत, आईआईआईडीईएम और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के सहयोग से, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में जिला चुनाव अधिकारी , मतदाता पंजीकरण अधिकारी, विषयगत विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों और चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्यों सहित 480 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं.

भारत में पब्लिक वाई-फाई बन सकता है ब्रॉडबैंड का पूरक

नई दिल्ली, 3 जून। नीति थिंक-टैंक ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) ने बुधवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के उस दृष्टिकोण का स्वागत किया, जिसमें पब्लिक वाई-फाई को सस्ती और सर्वसुलभ ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई है.

ट्राई की मान्यताज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने पब्लिक वाई-फाई को सस्ती और सर्वसुलभ ब्रॉडबैंड सेवा का महत्वपूर्ण पूरक माना. बीआईएफ की सिफारिश- ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने कहा कि केवल मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, पब्लिक वाई-फाई कनेक्टिविटी और स्पेक्ट्रम दक्षता बढ़ा सकता है.

मिशन 2027 | **मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में व्यापक फेरबदल, कई नेताओं को नई जिम्मेदारी.**

योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक दांव

- यूपी में जिलों का नया समीकरण, मंत्रियों को कमान
- सरकार ने बदले कई जिलों के प्रभारी मंत्री

लखनऊ, 3 जून. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में व्यापक फेरबदल किया है. सरकार के इस फैसले के तहत कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ-साथ हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नेताओं को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

राजनीतिक और प्रशासनिक

हलकों में इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नई व्यवस्था के अनुसार कई मंत्रियों को उनके मौजूदा प्रभार के साथ अतिरिक्त जिलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. सरकार का उद्देश्य जिलों में बेहतर समन्वय स्थापित करना, विकास योजनाओं की निगरानी को मजबूत बनाना और जनसंपर्क को अधिक प्रभावी करना बताया जा रहा है. इसके साथ ही संगठन और सरकार के बीच तालमेल को और मजबूत करने की दिशा में भी यह कदम अहम माना जा रहा है. फेरबदल में प्रदेश के कई प्रमुख जिलों को नए प्रभारी मंत्री मिले हैं. अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, मेरठ, रायबरेली, गाजियाबाद और झांसी जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों में भी नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं. हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल हुए कुछ नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिलों का प्रभार देकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उन्हें संगठनात्मक भूमिका में भी सक्रिय किया जाएगा.

5 प्रमुख बातें....

1. योगी सरकार ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बड़ा फेरबदल किया.
2. कई वरिष्ठ और नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं.
3. अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज जैसे अहम जिलों में बदलाव हुआ.
4. सरकार का फोकस बेहतर समन्वय और विकास कार्यों की निगरानी पर है.
5. फैसले को मिशन 2027 की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा.

'क्वांट' इस्तेमाल करेगी यूरोपीय संसद

ब्रसेल्स, 03 जून. यूरोपीय संसद इस सप्ताह अपने कंप्यूटरों में गूगल की जगह फ्रांस के सर्च इंजन क्वांट को डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में अपनाने जा रही है. यह कदम यूरोप की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने और अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संसद ने अपने सदस्यों को भेजे गये एक ई-मेल में बताया है कि गुरुवार से फायरफॉक्स और एज ब्राउजर के एड्रेस बार में किये जाने वाले सर्च के परिणाम क्वांट के माध्यम से प्राप्त होंगे. ई-मेल में कहा गया है कि क्वांट एक गोपनीयता-केंद्रित यूरोपीय सर्च

इंजन है, जिसे उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को ट्रैक किये बिना और व्यक्तिगत डेटा एकत्र किये बगैर खोज सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है, जब यूरोपीय आयोग बुधवार को डिजिटल संप्रभुता बढ़ाने और अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से नये कानूनी प्रस्तावों का एक पैकेज पेश करने वाला है. यूरोपीय संसद ने कहा कि यह बदलाव संस्था की डिजिटल संप्रभुता और उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है.

सांसदों को सर्च इंजन चुनने की स्वतंत्रता रहेगी

सांसदों को गूगल सहित अपनी पसंद का अन्य सर्च इंजन चुनने की स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन डिफॉल्ट विकल्प के रूप में क्वांट उपलब्ध होगा. क्वांट का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी पहले अपने खोज परिणामों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के बिंग इंडेक्स पर निर्भर थी, लेकिन हाल के वर्षों में उसने यूरोपीय सर्च प्लेटफॉर्म इकोसिया के साथ मिलकर अपना स्वतंत्र सर्च इंडेक्स स्टान विकसित करना शुरू किया है.

कोलकाता मेयर पद से फिरहाद हकीम ने दिया इस्तीफा

कोलकाता, 3 जून. पश्चिम बंगाल की सियासत में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है. यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब पार्टी पहले से ही अभूतपूर्व राजनीतिक संकट का सामना कर रही है. टीएमसी के भीतर बढ़ती असहमति और बागी नेताओं की सक्रियता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. विधानसभा में 58 बागी विधायकों के नए गुट को मान्यता मिलने के बाद पार्टी की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.